

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र संख्या ३/२०२२

गीता राम नौटियाल

..... आवेदक

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी

उपस्थित:-

श्री किशोर कुमार, अधिवक्ता श्री एन.के. पपनै के पक्षाधारक

श्री पंकज जोशी, राज्य/प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्षाधारक।

श्री सी.के.शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या २

माननीय न्यायमूर्ति, रविन्द्र मैठाणी (मौखिक)

निज प्रत्यर्थी चन्द्रशेखर करगेती को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में, "एससी/एसटी एक्ट"), की धारा 3 (1) (पी) और 3 (1) (क्यू) के तहत 2016 के केस क्राइम नंबर 102, पुलिस स्टेशन वसंत विहार, जिला देहरादून जमानत आवेदन संख्या 2118/ 2021 चंद्र शेखर करगेती बनाम राज्य उत्तराखंड, में 24.11.2021 को विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देहरादून द्वारा जमानत दी गयी। आवेदक जमानत रद्द करने की मांग करता है।

2. पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

3. इस मामले का इतिहास संक्षेप में निम्नानुसार है-

(i) 2016 के केस अपराध संख्या 102 के तहत

एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (पी) और 3 (1) (क्यू), पुलिस स्टेशन वसंत विहार, जिला देहरादून में अन्वेषण के बाद निजी प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया जिसके आधार पर दिनांक 30.01.2017 को देहरादून के सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अधिनियम के न्यायालय ने 2017 के विशेष सत्र विचारण संख्या 4 राज्य बनाम चंद्रशेखर में अपराध का संज्ञान लिया।

- (ii) दिनांक 30.01.2017 के संज्ञान और समन आदेश को निजी प्रत्यर्थी द्वारा प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र (सी -482) संख्या 576/2017 में इस न्यायालय ("पहली याचिका") के समक्ष चुनौती दी गई थी।
- (iii) पहली याचिका को आदेश दिनांकित 08.08.2018 के अन्तर्गत 2 लाख की राशि के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया था।
- (iv) दिनांक 08.08.2018 के इस आदेश को निजी प्रत्यर्थी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 की विशेष अनुमति याचिका आपराधिक संख्या 6939/2018 (सीआरएल) ("पहली एसएलपी"), दिनांक 20.10.2021 को खारिज कर दिया गया था, लेकिन हर्जाने को कम कर दिया गया था।
- (v) पहली एसएलपी में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 20.10.2021 के आदेश के तहत निजी प्रत्यर्थी को उस दिनांक से दो सप्ताह के भीतर संबंधित न्यायालय से उपागम करने की अनुमति दी और तब तक, उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किये जाने के निर्देश पारित किये।

- (vi) निजी प्रत्यर्थी ने पहली एसएलपी में दिनांक 20.10.2021 को पारित आदेश के खिलाफ पुर्नविलोकन याचिका दायर की जिसे दिनांक 11.01.2022 को खारिज कर दिया गया था।
- (vii) निजी प्रत्यर्थी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन इस न्यायालय में करता है, जिसे एबीए नंबर 230/2021 के द्वारा पंजीकृत किया गया था।
- (viii) निजी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका का दिनांक 26.10.2021 को निस्तारण किया गया निजी प्रत्यर्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश होने के आदेश दिये गये थे तथा यह भी टिप्पणी की कि यदि निज प्रत्यर्थी न्यायालय में उपस्थित होता है और जमानत के लिए आवेदन करता है तो न्यायालय सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 922 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार उक्त जमानत आवेदन पर फैसला करेगी।
- (ix) निजी प्रत्यर्थी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2119/2021 विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989/ पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देहरादून, के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे 23.11.2021 को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने उस आदेश में यह भी कहा कि पत्यर्थी की नियमित जमानत याचिका को दिनांक 24.11.2021 को सुना जायेगा इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित सतेन्द्र कुमार अंतिल के निर्देशों के

पालनानुसार निजी प्रत्यर्थी को अभिरक्षा में लिए बिना सुना जाएगा। दिनांक 24.11.2021 को, न्यायालय ने निजी प्रत्यर्थी को जमानत प्रदान की ।

(x) इस न्यायालय के द्वारा एबीए संख्या 230/2021 में पारित दिनांकित 26.10.2021 के आदेश को आवेदक द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एसएलपी संख्या (सीआरएल) संख्या 30317/2021 ("दूसरी एसएलपी") में चुनौती दी गई थी, जिस पर 03.01.2022 को निर्णय लिया गया था। माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: –

पीठ ने कहा, "विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है। हम यह धारित करते हुए इस विशेष अनुमति याचिका का निस्त'रण करते हैं कि विचारण न्यायालय को 26.10.2021 की इस विशेष अनुमति याचिका में अक्षेपित आदेश से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष के आधार पर और विधि के अनुसार जमानत आवेदन पर फैसला करें। यदि विचारण न्यायालय पहले ही आदेश पारित कर चुका है, तो वह उचित संक्षम न्यायालय समक्ष उस आदेश को चुनौती दे सकता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उसे निस्तारित समझा जाय।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि इस मामले में आवेदक को अभिरक्षा में लिया जाना चाहिए था क्योंकि अपराध अपराधों की श्रेणी "सी" में आता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सतेंद्र कुमार एंटिल ((उपर्युक्त)) के मामले में निर्दिष्ट किया गया है

5. यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपराध को "ए" श्रेणी के तहत आने वाले अपराध के रूप में मानने में त्रुटि की।

6. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वास्तव में, सतेंद्र कुमार अंतिल के मामले में ((उपर्युक्त)), जब श्रेणी "सी" के तहत अपराधों को वर्गीकृत किया गया, अंतिम शब्द "आदि" का उपयोग किया गया है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इसका मतलब है कि विशेष अधिनियमों के तहत सभी अपराध इसमें शामिल हैं। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि 24.11.2021 का जमानत आदेश, जो निज प्रत्यर्थी को अभिरक्षा में लिए बिना पारित किया गया है, विधि की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण है। विद्वान अधिवक्ता ने निरंजन सिंह और एक अन्य बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे और अन्य (1980)2 एससीसी 559 के मामले में निर्धारित विधि के सिद्धांत का भी उल्लेख किया है।

7. निरंजन सिंह (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने "अभिरक्षा" शब्द पर चर्चा की और पैरा 8 में निम्नानुसार देखा गया: –

"8. धारा 439 के संदर्भ में अभिरक्षा (जैसा कि हम ध्यान दें, धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत से संबंधित नहीं हैं) न्यायालय में अभियुक्त की शारीरिक नियंत्रण या कम से कम शारीरिक उपस्थिति के साथ, जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और आदेशों के अधीन रहने से सम्बन्धित है।

8. निरंजन सिंह (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रेषित किया कि "वह केवल तब अभिरक्षा में नहीं माना जायेगा। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है और न्यायिक या अन्य अभिरक्षा में रिमांड प्राप्त करती है। उसे न्यायिक अभिरक्षा में तब भी कहा जा सकता है जब वह न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है और उसके निर्देशों का पालन करता है।

9. दूसरी ओर, निजी प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यदि कोई अभियुक्त न्यायालय के समक्ष पेश होता है, तो यह अभिरक्षा के समान है, किसी औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? क्या निजी प्रत्यर्थी की जमानत याचिका

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी? यह कथित किया गया कि फलस्वरूपित निजी प्रत्यर्थी को अभिरक्षा में ले लिया गया होगा।

10. यह तर्क दिया गया कि मामले में कोई अवैधता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने संदीप कुमार बाफना बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2014)16 एससीसी 623 के मामले में निर्धारित विधि के सिद्धांत का तर्क दिया।

11. संदीप कुमार बाफना (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है। निरंजन सिंह (उपर्युक्त) के मामले में निर्धारित कानून इस मामले में पालन किया गया है। पैरा 24 और 33 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: –

"24. इस विश्लेषण में, आक्षेपित निर्णय [संदीप कुमार बाफना बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2014 का आपराधिक जमानत आवेदन संख्या 206/2014 दिनांक 6-2-2014 (बोम्बे)] में त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालती है कि उच्च न्यायालय एक याचिका पर अधिकार क्षेत्र से वंचित या रहित है जो पहले आत्मसमर्पण की दलील देता है और उसके बाद, जमानत के लिए प्रार्थना करता है। उच्च न्यायालय लापरवाही से अपीलकर्ता को अपनी अभिरक्षा में ले सकता था और फिर जमानत के लिए अनुरोध के अवलोकन के साथ आगे बढ़ सकता था; इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में कि जमानत पर विस्तार के लिए पर्याप्त आधार का खुलासा नहीं किया गया था, न्यायिक या पुलिस अभिरक्षा के लिए आवश्यक आदेश निर्धारित किए जा सकते थे। एक न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी सार्वजनिक दबाव के बिना अपने कर्तव्यों का प्रबलता से निर्वहन करें।

33. इसलिए, निष्कर्षतः हमारी राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह धारित करते हुए त्रुटि की कि वह अपीलकर्ता के प्रार्थना पत्र को सुनने के क्षेत्राधिकार से वंचित था। वैचारिक रूप से, वह न्यायालय की अभिरक्षा में आत्मसमर्पण करने के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर सकता था, हालांकि, हम वर्तमान में इस

विकल्प का उपयोग करने के किसी भी कारण से अवगत नहीं हैं। एक बार आत्मसमर्पण के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो हमारे सामने अपीलकर्ता धारा 439 सीआरपीसी के तहत न्यायालय की अभिरक्षा में आ जाएगा। सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय, जो धारा 439 के तहत समवर्ती शक्तियों का प्रयोग करते हैं तब मामले के गुण-दोष पर जा सकते हैं ताकि यह निर्णित किया जा सके कि आवेदक-अपीलकर्ता ने जमानत पर रिहा होने के लिए पर्याप्त कारण या आधार दिखाया है या नहीं।"

12. एक अन्य पहलू पर, निजी प्रत्यार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि तत्काल मामला में अपराध "सी" श्रेणी में नहीं आता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल (*उपर्युक्त*) के मामले में निर्दिष्ट किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि श्रेणी "सी" में अंत में उपयोग किए गए "आदि" शब्द का अर्थ सभी विशेष अधिनियमों को शामिल करना नहीं है। लेकिन, यह तर्क दिया गया कि "आदि" शब्द केवल ऐसे विशेष अधिनियमों के लिए प्रयुक्त किया गया जिनमें जमानत के लिए कड़े प्रावधान हैं। तर्क दिया गया कि एससी/एसटी एक्ट जमानत के लिए कोई कड़े प्रावधान नहीं करता है। अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के तहत मामलों में जमानत दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1973 के प्रावधानों द्वारा निर्धारित होती है।

13. क्या निजी प्रत्यार्थी को 24.11.2021 को अभिरक्षा में लिया गया था, जब उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी? यह स्वीकृत है कि वह उस तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे।

14. जहां तक अभिरक्षा का प्रश्न है, निरंजन सिंह (*उपर्युक्त*) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 8 में स्पष्ट रूप से कहा कि अभिरक्षा का अर्थ है न्यायालय में अभियुक्त पर शारीरिक नियंत्रण या कम से कम उसकी न्यायालय में शारीरिक उपस्थिति जिसके साथ न्यायालय के क्षेत्राधिकार की अधीनता युग्मित है। इसके साथ युग्मित शब्द महत्वपूर्ण है। केवल उपस्थिति शायद

अभिरक्षा के समान नहीं हो सकती है। पैरा 9 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे और अर्हता प्रदान की और कहा कि, "उसे तब न्यायिक अभिरक्षा में कहा जा सकता है जब वह न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर उसके आदेशों के अधीन रहता है। यह केवल उपस्थिति नहीं है, बल्कि आत्मसमर्पण और निर्देशों के अधीनता की अभिव्यक्ति है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संदीप कुमार बाफना (उपर्युक्त) के मामले में यही बात दोहराई है।

15. इस मामले में, जैसा कि कहा गया है, हालांकि निजी प्रत्यार्थी 24.11.2021 को न्यायालय के समक्ष पेश हुआ, लेकिन क्या उसने न्यायालय के निर्देशों के सामने आत्मसमर्पण करने का आशय व्यक्त किया? इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। न्यायालय इस विवादक को कि क्या आवेदक अभिरक्षा में था या नहीं, तथ्यात्मक रूप से निर्धारित किये बिना यथास्थिति पर रखती है।

16. विचाराधीन प्रश्न यह है कि जैसा कि सतेंद्र कुमार अंतिल (उपर्युक्त) के मामले में वर्गीकृत श्रेणी "सी" के अपराधों में जिस "आदि" शब्द का प्रयोग किया गया है, उसमें एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध को शामिल होने चाहिए या नहीं।

17. सतेंद्र कुमार अंतिल (उपर्युक्त) के निर्णय के पैरा 3 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामलों को निम्नानुसार चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:-

"3. हम दिशानिर्देशों को स्वीकार करने और उन्हें अधीनस्थ न्यायालयों के लाभ के लिए न्यायालय के आदेश का हिस्सा बनाने के इच्छुक हैं। दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं-

"अपराधों की श्रेणियाँ/प्रकार

(A) 7 वर्ष या उससे कम के कारावास के साथ दंडनीय अपराध जो श्रेणी बी और डी में नहीं आते हैं।

(B) मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराध।

(C) जमानत के लिए जिसमें कड़े प्रावधान हैं जैसे विशेष अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराध जैसे एनडीपीएस (धारा 37), पीएमएलए (धारा 45), यूएपीए [धारा 43 डी (5), कंपनी अधिनियम [धारा 212 (6)], आदि।

(D) आर्थिक अपराध जो किसी विशेष अधिनियम के अर्न्तगत नहीं आता

18. श्रेणी "सी" के तहत कुछ निर्दिष्ट विशेष अधिनियमों का सतेंद्र कुमार अंतिल (*उपर्युक्त*), के मामले में उल्लेख किया गया है लेकिन इससे पहले कि विशेष अधिनियमों को विस्तृत किया जाए, शुरुआती शब्द महत्वपूर्ण हैं, वे हैं, "जमानत के लिए कड़े प्रावधानों वाले विशेष अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराध" और इस खंड "सी" के अंत में एक शब्द "आदि" का उपयोग किया गया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, "आदि" शब्द का अर्थ है "वगैरह"। इसका मतलब है, और इसी तरह की अन्य चीजें; और इसी तरह।

19. वास्तव में, मैसर्स ग्लैमर कटक बनाम ओडिशा राज्य, 2013 के एसटीआरईवी संख्या 8, उड़ीसा राज्य के लिए, निर्णय के पैरा 11 से 15 में, "आदि" शब्द पर निम्नानुसार चर्चा की गई है: –

"11. "आदि" शब्द *कॉलिज अंग्रेजी भाषा के थिसॉरस*, तीसरा संस्करण 2008, पृष्ठ -343 में परिभाषित किया गया है "और इसी तरह, और आगे आदि" के रूप में। कानूनी भाषा में, *ब्लैक लॉ डिक्शनरी* (8 वां संस्करण, 2004) पृष्ठ 592 अभिव्यक्ति आदि को "और अन्य चीजों" के रूप में परिभाषित किया गया है; यह शब्द आमतौर पर एक श्रृंखला में अतिरिक्त, अनिर्दिष्ट वस्तुओं को इंगित करता है"।

12. भारतीय संदर्भ में *पी. रामनाथ अय्यर, कानून लेक्सिकॉन*

(दूसरा संस्करण पुनर्मुद्रण 2008 पृष्ठ -678), इसे इस प्रकार परिभाषित करता है:

"आदि या & C. एट वगैरह का संक्षिप्त नाम है, और इसलिए इसका अर्थ और अन्य, आदि हो सकते हैं; और बाकी; अन्य बातें; एक ही चरित्र के, या केवल उन चीजों के बारे में जो एक ही हैं। रिवाज, पक्षकारों का आशय, संदर्भ, और जिस तरह से और स्थान में संक्षिप्त नाम का उपयोग किया जाता है, वह इसके अर्थ को नियंत्रित कर सकता है; लेकिन जहां इसका एक निश्चित अर्थ हो सकता है, इसे वह अर्थ दिया जाएगा; हालांकि कभी-कभी इसका उपयोग किया जाता है, इसे अर्थहीन और प्रभाव के बिना माना जाता है, और अक्सर अधिशेष के रूप में अवहेलना की जाती है।

13. **राजगोपाल पंडाराथर बनाम थिरुपाथिया पिल्लई एआईआर 1923 मद्रास 511** बंधक-विलेख में उपयोग किए गए शब्द, व्याख्या के लिए आए जिन पर वाद आधारित था। प्रश्न यह था कि क्या पहले प्रत्यर्थी का निवास डिक्री में निहित विवरण में शामिल किया गया था? वादी ने बंधक-विलेख में निम्नलिखित पंक्ति में होने वाले 'वगैरह' शब्द पर बल दिया ताकि यह तर्क दिया जा सके कि प्रत्यर्थी के निवास को शामिल किया जाएगा।

"मेरे पास बंजर भूमि, पोरामबोके और उससे जुड़ी अन्य भूमि में, सभी प्रकार के पेड़, टोपे, कुएं, तालाब, टैंक-बांध, फलों के पेड़, लकड़ी के पेड़, पैदल मार्ग, ऊंचे और निचले हिस्से आदि, चाहे वे थोड़े अधिक या थोड़े कम हों, प्रत्यभूति के रूप में दिए गए हैं।

14. मद्रास उच्च न्यायालय वादी की दलील से सहमत नहीं हुआ और कहा:

"लेकिन एकमात्र तर्क दिया गया कि महल की इमारत को 'शेष भूमि' या 'पोरम्बोके और अन्य भूमि' या 'आदि' शब्दों में शामिल किया जाना चाहिए। मुझे यह मानना असंभव लगता है कि 'शेष भूमि' या 'पोरम्बोक और उससे जुड़ी अन्य भूमि (शेष भूमि)' शब्दों को जमींदार की आवासीय इमारत सहित माना जा सकता है।

शब्द 'आदि', वे एक गणना का पालन करते हैं। "सभी प्रकार के पेड़ों" से शुरू होने वाली विशिष्ट चीजों की संख्या कुछ विशेषताएं हैं, और शब्द होने चाहिए उसी प्रकृति की चीजों तक सीमित है जो उन लोगों के समान हैं जो पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। ऐसे में नियम एजुस्टेम

जेनेरिस लागू होंगे और आवासीय इमारत को इमारत के साथ एजुस्डेम जेनेरिस नहीं कहा जा सकता है। पहले से ही उल्लिखित चीजें।"

15. **के.वी. मैथ्यू बनाम जिला प्रबंधक, टेलीफोन, एर्नाकुलम, एआईआर 1984 केर 40**, उच्च न्यायालय 'संस्था' अभिव्यक्ति पर विचार कर रहा था और अभिव्यक्ति के दायरे के संदर्भ में, यह माना गया था कि "शब्द वगैरह समावेशी परिभाषा के चरित्र को साझा नहीं करता है और 'संस्था' शब्द की अभिव्यक्ति के दायरे को बड़ा नहीं सकता

20. "आदि" शब्द का शाब्दिक अर्थ, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि जब "आदि" शब्द का उपयोग किया जाता है तो इसका उपयोग समान प्रकार की चीजों के लिए किया जाता है या केवल उन चीजों के लिए किया जाता है जो पहले से ही वर्णित की गई चीजों के साथ समान हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान, विश्वविद्यालय बनाम सचित प्रसारक मंडल और अन्य, (2010)3 एससीसी 786 के मामले में एजुस्डेम जेनेरिस के नियम पर चर्चा की गई थी। निर्णय के पैरा 27, 28, 31 और 32, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

लैटिन अभिव्यक्ति "एजुस्डेम जेनेरिस" जिसका अर्थ है "एक ही प्रकार या प्रकृति का" निर्माण का एक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि जब एक वैधानिक पाठ में सामान्य शब्द प्रतिबंधित शब्दों से घिरे होते हैं, तो सामान्य शब्दों के अर्थ को प्रतिबंधित शब्दों के अर्थ के साथ निहितार्थ द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। यह एक सिद्धांत है जो "भाषाई निहितार्थ से उत्पन्न होता है जिसके द्वारा शाब्दिक रूप से व्यापक अर्थ वाले शब्दों (जब अलगाव में लिया जाता है) को मौखिक संदर्भ द्वारा दायरे में कम माना जाता है"। इसे एलिप्सिस का एक उदाहरण माना जा सकता है, या निहितार्थ पर निर्भरता। इस सिद्धांत को तब तक लागू माना जाता है जब तक कि कुछ विपरीत संकेत न हों, ग्लेनविले विलियम्स, एजुस्डेम जेनेरिस नियम की उत्पत्ति और तार्किक निहितार्थ, 7 कन्व (एनएस) 119।

28. यह एजुस्डेम जेनेरिस सिद्धांत नोसिटूर ए सोसिस के सिद्धांत का एक पहलू है। लैटिन मैक्सिम नोसिटूर ए सोसिस का अर्थ है कि एक

वैधानिक शब्द को उसके संबंधित शब्दों द्वारा पहचाना जाता है। लैटिन शब्द "सोसाइटी" का अर्थ है "समाज"। इसलिए, जब सामान्य शब्दों को विशिष्ट शब्दों के साथ जोड़ा जाता है, तो सामान्य शब्दों को अलगाव में नहीं पढ़ा जा सकता है। उनका रंग और उनकी सामग्री उनके संदर्भ से ली जानी चाहिए। (अटॉर्नी जनरल बनाम प्रिंस अर्नेस्ट ऑगस्टस ऑफ हनोवर [1957 एसी 436: (1957) 2 डब्ल्यूएलआर 1: (1957) 1 ऑल ईआर 49 (एचएल)] में विस्काउंट सिमोंड्स के इसी तरह की टिप्पणी का अवलोकन करें।

31. इस न्यायालय ने एजुस्टेम जेनेरिस के सिद्धांत का निर्माण करते हुए कवलप्पारा कोट्टारथिल कोचुनी बनाम मद्रास राज्य आईआर 1960 एससी 1080 में भी इसी तरह के सिद्धांत को निर्धारित किया था। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कोचुनी [एआईआर 1960 एससी 1080] में न्यायमूर्ति सुब्बा राव, के माध्यम से बोलते हुए यह धारित किया (एआईआर पी. 1103, पैरा 50)

"50. ... नियम यह है कि जब सामान्य शब्द एक ही प्रकृति के विशेष और विशिष्ट शब्दों का पालन करते हैं, तो सामान्य शब्दों को उसी तरह की वस्तुओं तक सीमित होना चाहिए जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से तय किए गए मामलों द्वारा निर्धारित किया गया है कि विशिष्ट शब्दों को एक अलग जीनस या श्रेणी बनाना चाहिए। यह कानून का अनुल्लंघनीय नियम नहीं है, परन्तु *इसके विपरीत संकेत के अभाव में* केवल अनुमेय अनुमान है।

32. इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अमर चंद्र चक्रवर्ती बनाम आबकारी कलेक्टर (1972) 2 एससीसी 442 : एआईआर 1972 एससी 1863 ने न्यायमूर्ति दुआ के माध्यम से रिपोर्ट के पृष्ठ 1868 के पैरा 9 में उन्हीं सिद्धांतों को दोहराया। एजुस्टेम जेनेरिस के सिद्धांत पर, विद्वान न्यायाधीश ने निम्नानुसार टिप्पणी की: (एससीसी पी। 447, पैरा 9)

"9. ... एजुस्टेम जेनेरिस नियम विशिष्ट और सामान्य शब्दों के बीच असंगति के सामाधान को समेटने का प्रयास करता है। यह सिद्धांत तब लागू होता है जब (i) कानून में विशिष्ट शब्दों की गणना होती है; (ii) गणना के विषय एक वर्ग या श्रेणी का गठन करते हैं; (iii)

वह वर्ग या श्रेणी गणना से समाप्त नहीं हुई है; (iv) सामान्य शब्द गणना का अनुसरण करता है; और (v) अन्य वैधानिक आशय का कोई संकेत नहीं है”

21. राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, जयपुर बनाम मोहन लाल और अन्य एआईआर 1967 एससी 1857 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी एजुस्टेम जेनेरिस के नियम पर चर्चा की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पैरा 4 में निम्नानुसार टिप्पणी की: –

"4. हमारी राय में, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 12 में "अन्य प्राधिकरण" शब्द की व्याख्या करते समय एजुस्टेम जेनेरिस के सिद्धांत को त्रुटिपूर्ण लागू किया क्योंकि उन्होंने व्याख्या के मूल सिद्धांत की अनदेखी की कि, एजुस्टेम जेनेरिस नियम को लागू करने के लिए, पहले से नामित निकायों के माध्यम से एक अलग जीनस या श्रेणी होनी चाहिए। **क्रेस, संविधि कानून** सिद्धांत को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत करता है:

'एजुस्टेम जेनेरिस नियम को सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए और इसे बहुत दूर नहीं धकेला जाना चाहिए... एजुस्टेम जेनेरिस के नियम को लागू करने के लिए एक अलग जीनस या श्रेणी होनी चाहिए। विशिष्ट शब्दों को व्यापक रूप से भिन्न चरित्र की विभिन्न वस्तुओं पर लागू नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी ऐसी चीज़ पर लागू होना चाहिए जिसे वर्ग या प्रकार की वस्तुएं कहा जा सकता है। जहां इसकी कमी है, वहां नियम लागू नहीं हो सकता है, लेकिन एक एकल प्रजाति का उल्लेख एक जीनस का गठन नहीं करता है [संविधि कानून पर **क्रेस, 6 वां संस्करण, पृष्ठ 181**] ।

मैक्सवेल ने अपनी पुस्तक 'विधियों की व्याख्या' में सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा: "लेकिन सामान्य शब्द जो एक ही प्रकृति के विशेष और विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करता है, वह उनसे अपना अर्थ लेता है, और माना जाता है कि यह उन शब्दों के समान जीनस तक ही सीमित है ... जब तक कोई जीनस या श्रेणी नहीं है, तब तक एजुस्टेम जेनेरिस सिद्धांत के लागू होने के लिए कोई जगह नहीं है विधियों की व्याख्या पर मैक्सवेल, 11 वां एडन पीपी 326, 327 यूनाइटेड

टाउन्स इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड बनाम न्यूफ़ाउंडलैंड के अटॉर्नी-जनरल [(1939) आई एईआर 423], प्रिवी काउंसिल ने माना कि, उनकी राय में, जीनस के किसी भी उल्लेख के अभाव में एजुस्टेड जेनेरिस के सिद्धांत को लागू करने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि एक ही प्रजाति का उल्लेख - उदाहरण के लिए, पानी की दर - एक जीनस का गठन नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 12 में, विशेष रूप से नामित निकाय संघ और राज्यों की कार्यकारी सरकारें, संघ और राज्यों के विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकरण हैं। हम इन नामित निकायों के माध्यम से चलने वाले किसी भी सामान्य जीनस को खोजने में असमर्थ हैं, न ही इन निकायों को किसी भी तर्कसंगत आधार पर एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है। इसलिए, इस लेख में "अन्य प्राधिकरण" की अभिव्यक्ति की व्याख्या के लिए एजुस्टेड जेनेरिस के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है।

22. स्थापित कानून के मद्देनजर, ऐसे संदर्भ में "आदि" शब्द का अर्थ अनिर्देशित नहीं है, लेकिन यह हमेशा जो इससे पहले आता है। उसके साथ ही समझा जाता है।
23. श्रेणी "सी" में जैसा कि सतेंद्र कुमार अंतिल (*उपर्युक्त*) के मामले में परिभाषित किया गया है विभिन्न विशेष अधिनियम बनाए गए हैं, लेकिन वे केवल विशेष अधिनियम नहीं हैं, किन्तु अन्य प्रावधानों के अधीन हैं। वे विशेष अधिनियम इन शब्दों के साथ योग्य हैं, "जमानत के लिए कड़े प्रावधान शामिल हैं जैसे" इसलिए, "आदि" शब्द केवल ऐसे विशेष अधिनियमों के लिए योग्य है, जिसमें जमानत के लिए कड़े प्रावधान थे। इसलिए, विधायिका का आशय श्रेणी "सी" में उपयोग किए गए "आदि" की ऐसी व्याख्या करने का नहीं हो सकता है जो प्रत्येक विशेष अधिनियम को इस श्रेणी में लाये। सतेंद्र कुमार अंतिल (*उपर्युक्त*) के मामले में श्रेणी "सी" में "आदि" शब्द की व्याख्या केवल ऐसे विशेष अधिनियमों को शामिल करने के लिए की जानी चाहिए जिनमें जमानत के लिए कड़े प्रावधान हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के मामले में

ऐसा कोई कठोर प्रावधान नहीं है। इसलिए, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि एससी/एसटी अधिनियम "सी" श्रेणी में नहीं आता है।

24. (उपर्युक्त) के प्रकाश में इस न्यायालय का यह विचार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की। जमानत का आदेश विधि के अनुसार है। इसलिए जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
25. जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(रवींद्र मैठाणी, न्यायमूर्ति।

01.10.2022

संजय